भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1850
30 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षमता वृद्धि

1850. **श्री भर्तृहरि महताबः**
श्री भोजराज नागः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री आशीष दुबेः
श्री बलभद्र माझीः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती मालविका देवीः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्यवर्धन किए जाने और प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करने में हुई प्रगति क्या है और देश में तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी पहलों की स्थिति क्या है;
(ख) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए मंत्रालय की विभिन्न पहलों के ज़रिए किए गए निवेश तथा ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) मंत्रालय द्वारा मोटे अनाज/मिलेट से बने उत्पाद और अन्य प्राथमिकता वाले उत्पाद जैसे मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में देश और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में की गई पहलें क्या हैं; और
(घ) इन पहलों के अंतर्गत सृजित रोज़गार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और देश में तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों और सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या कितनी है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं मांग-आधारित हैं और ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।दिनांक 30.06.2026 तक, देश भर में 1735 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 9258.60 करोड़ रुपये की स्वीकृत सहायता अनुदान और लगभग 23904.74 करोड़ रुपये का निजी निवेश शामिल है, जिसमें से 12 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं, जिसमें 101.61 करोड़ रुपये की स्वीकृत सहायता अनुदान और लगभग 222.69 करोड़ रुपये का निजी निवेश शामिल है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत 1256 परियोजनाएं पूर्ण/परिचालन में हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में 241.55 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) प्रति वर्ष प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है, जिसमें से 6 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य में हैं जिनकी प्रसंस्करण क्षमता 1.51 एलएमटी प्रति वर्ष है। इसके अलावा, ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 परियोजनाएं स्थित हैं, जिनके लिए 23.62 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान स्वीकृत है और लगभग 54.67 करोड़ रुपये का निजी निवेश है। सभी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिससे 1.43 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) प्रति वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता निर्मित हुई है।

पीएलआईएसएफपीआई का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुविधाजनक बनाना है। दिनांक 30.06.2026 की तक, देश भर में 212 स्थानों पर 127 कंपनियों के 163 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 7,722 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के मुकाबले 9,207 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश हुआ है। इनमें से 1 प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जिसमें 45.14 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश हुआ है। ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र में पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 30.06.2026 तक, देश भर में 200421 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को 5954.57 करोड़ रुपये की ऋण-लिंक्ड सब्सिडी और लगभग 14480.24 करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ स्वीकृति दी गई है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में 1941 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को 84.04 करोड़ रुपये की ऋण-लिंक्ड सब्सिडी और 255.79 करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 9.05 करोड़ रुपये की ऋण-लिंक्ड सब्सिडी और 31.62 करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ 172 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ): मिलेट और अन्य प्राथमिकता वाले उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, एमओएफपीआई अपनी तीन योजनाओं के माध्यम से, ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पीएलआईएसएफपीआई योजना का एक घटक मिलेट-आधारित उत्पादों (एमबीपी) पर केंद्रित है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का परिव्यय है। मिलेट-आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलेट के उपयोग को बढ़ाना और घरेलू तथा निर्यात मिलेट्स में चयनित मिलेट-आधारित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करके

उनके मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है। वर्तमान तिथि तक, पीएलआईएसएमबीपी के लिए कुल 800 करोड़ रुपये के आवंटन में से, 29 आवेदकों को प्रोत्साहित करने के लिए 793.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 8 बड़े और 21 लघु एवं मध्यम उद्यम शामिल हैं।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, देश के 21 जिलों में मिलेट आधारित उत्पादों को 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) के रूप में चिन्हित किया गया है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक, देश भर में मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 111.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 5515 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा क्षेत्र में 11.29 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ 5 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को स्वीकृति दी गई है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजना, 'खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार' (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत देश में मिलेट प्रसंस्करण की छह इकाइयों को स्वीकृति दी गई है।

एमओएफपीआई अपनी योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित पात्र संस्थाओं को सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान करता है। दिनांक 30.06.2026 तक, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत देश भर में परिचालन परियोजनाओं से 9.16 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिनमें से 4249 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सृजित हुए हैं।

दिनांक 30.06.2026 तक, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत देश भर में 6.01 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं, जिनमें से 516 ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं।

दिनांक 30.06.2026 तक, पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत देश भर में 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

*****